हिंदू संगठन ने निकाली रामनवमी पर हत्यारे शंभूलाल रैगर की झांकी, कहा भगवान राम की तरह सम्मान का हकदार है वह

कैसा समाज है हमारा जिसका आदर्श है हत्यारा शंभूलाल रैगर?

जयपुर, जनज्वार। पिछले साल राजसमंद में एक मुस्लिम के लाइव मर्डर को नृशंसता से अंजाम देने वाले शंभूलाल रैगर की हिंदू संगठन ने रामनवमी पर निकाली झांकी, उठने लगे सवाल कथित बहिन से अवैध संबंध जबरन रखने वाला शंभूलाल है हिंदू धर्म का आदर्श ?

हिंदू धर्म में आस्था के प्रतीक भगवान श्रीराम की झांकी प्रत्येक साल उल्लास से हिंदू समाज मनाता आ रहा है, मगर इस साल यह झांकी अपने आप में अनोखी थी। अनोखी इसलिए क्योंकि इस साल रामनवमी पर लाइव मर्डर को अंजाम देने वाले मानसिक विक्षिप्त की झांकी निकाली गई। जिस हत्यारे को फांसी पर लटका दिया जाना चाहिए था, उसे हिंदू संगठन ने समाज का आदर्श घोषित कर उसके सम्मान में झांकी तक निकाली।

गौरतलब है कि पिछले वर्ष राजस्थान के राजसमंद में राजस्थान में लव जिहाद के नाम पर नृशंसता से शंभूलाल रैगर ने मुस्लिम अफराजुल का न सिर्फ मर्डर किया, बल्कि अपने नाबालिग भतीजे से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करवा दिया था। लव जिहाद के नाम पर मुस्लिम का कत्ल करने वाले शंभूलाल के बारे में बाद में पुलिसिया जांच में उसकी पत्नी ने तक स्वीकारा था कि जिस कथित हिंदू बहिन के साथ अवैध संबंधों को लेकर उसने मुस्लिम को निर्ममता से मौत के घाट उतारा था, उस बहिन से उसने खुद जबरन न सिर्फ शारीरिक संबंध बनाए थे, बल्कि लंबे समय से जबरन उसे बंधक बनाया हुआ था।

उसी शंभूलाल को हिंदू संगठन ने अपना हीरो यानी भगवान राम के समकक्ष शामिल कर उसे अपना सार्वजनिक तौर पर उसकी झांकी निकाल उसके कुकृत्यों के लिए उसे साबाशी दी है।

झांकी के आगे लगे बैनर पर लिखा गया था, हिंदुओ भाइयो जागो, अपनी बहन-बेटी बचाओ। लव जिहाद से देश को आजाद करवाना चाहिए। इसी बैनर के एक हिस्से पर शंभूलाल रैगर की तस्वीर लगी हुई थी, जिसके नीचे लिखा था, 'शम्भूनाथ रैगर, लव जिहाद मिटाने वाले।'

मीडिया में आई खबरों के मुताबिक झांकी के आयोजक जोधपुर ईकाई के शिवसेना के सहकोषाध्यक्ष हरि सिंह पंवार कहते हैं, मैं रेगर के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता था। हिंदुत्व के प्रति उसकी प्रतिबद्धता ने मुझे प्रभावित किया है। हालांकि मेरा इरादा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का नहीं है।

गौरतलब है कि जब शंभूलाल रैगर ने लाइव मर्डर किया था तब मारे गए मुस्लिम मजदूर अफराजुल का वीडियो शेयर होने के बाद हिंदू संगठनों ने उसे खूब शाबासियां दीं। यही नहीं भाजपा का एक बूथ विस्तारक यानी बूथ स्तर का कार्यकर्ता प्रेम माली ने उसे डिफेंस और सही साबित करने के लिए %स्वच्छ राजसमंद, स्वच्छ भारत% वाट्सअप ग्रुप भी बनाया।

हिंदू धर्म के पवित्र पर्व रामनवमी पर हत्यारे शंभूलाल रैगर की झांकी को देख जहां कई लोग आक्रोशित थे, तो कई फूले नहीं समा रहे थे। जैसे ही शंभूलाल रैगर की झांकी वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर आईं, वायरल होते देर नहीं लगी।

ट्वीटर पर शंभूलाल की झांकी की वकालत करते हुए श्रेयांश नाम से ट्वीटर हेंडल से ट्वीट किया गया है, शंभु भैया से सिकलुर और मुस्लिम समुदाय क्यों चिढ़ता है जब साफ़ है उन्होंने एक लव जिहादी बांग्लादेशी को मारा न किसी भारतीय नागरिक मुस्लिम को? क्या आप बांग्लादेशी घुसपैठ व जिहाद का समर्थन करते हो अगर हाँ तो फिर तकिया कर भाईचारे की उम्मीद क्यों?

राम नवमी के मौके पर निकलने वाले जुलूस में हत्यारे शंभू को हिंदू धर्म के लिए सम्मान के रूप में पेश किया गया। इस झांकी के आयोजकों ने शंभूलाल रैगर को एंटी लव जेहाद के हीरो के बतौर पेश किया। कहा कि उसने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए लाइव मर्डर को अंजाम दिया।

झांकी में एक शख्स को शंभूलाल रैगर की तरह रूप धारण करा हाथों में कुल्हाड़ी लेकर बैठाया हुआ था। इतना ही नहीं आयोजकों ने झांकी के साथ बैनर पर तक लिखा था %हिंदुओ भाइयों जागो, अपनी बहन-बेटी बचाओ। लव जिहाद से देश को आजाद करवाना चाहिए।

खबर (दार) झरोखा

विवेक

सड़क बाप की, लूटना खून में- नितिन गडकरी

'मज़दूर मोर्चा' के लिये विशेष यात्रा विवरण

मेरा पैतृक गांव पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले के बांसगांव तहसील पाली (मड़ई) में है। मेरा जन्म एवं शिक्षा-दीक्षा दिल्ली में ही सम्पन्न हुई और गर्मियों की होने वाली विद्यालय की दो माह की छुट्टियों में रेल से गांव जाना एक सुखद अनुभव होता था।

हाल में, कुछ व्यक्तिगत कारणों से गांव जाना तय हुआ। सुबह-सुबह अपनी ही गाड़ी से 900 कि.मी. का सफ़र तय करने की हिम्मत की, क्योंकि भारतीय रेलवे की सीटें मुझे तो कभी भी अपने पूर्वी उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में जाने के लिये उपलब्ध नहीं हुई हैं। इतनी व्यस्त रेलवे लाइन को जहां कई ट्रैकों से लबरेज रहना चाहिए वहां दशा यह है कि ज़्यादातर हिस्सा सिंगल लाइन का ही है। इस लाइन से भी राजस्व भारत सरकार को मिलता होगा, विडम्बना देखिये यात्रियों को डबल ट्रैक तक मयस्सर नहीं।

इससे एक ओर जहां रेलगाड़ियों की संख्या कम रहती है वहीं सीटों की उपलब्धता भी घट जाती है। परिणामस्वरूप न तो यात्री समय पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सकते और न वापस आ सकते हैं। इससे सरकारी राजस्व का जो घाटा होता है वह अलग से।

खैर, सामान्य यात्रियों के लिये पूंजीवादी सरकारों का इतना करम भी बहुत है। रेल किरायों में बेतहाशा वृद्धि, सीटों की अनउपलब्धता, असुरक्षित रेलवे ट्रैक, एवं समय पर न पहुंचने की गारंटी के साथ 'असुविधा के लिये खेद है' जैसी घोषणा ने भारतीय यात्री को रेल से निकालकर सड़क पर फेंक दिया है। ठीक उसी प्रकार जैसे कभी गांधी जी को फर्स्ट क्लास से निकालकर प्लेटफ़ार्म पर पटक दिया गया होगा।

खैर, दिल्ली से, कार से निकलते ही नोएडा एक्सप्रेस वे पर जाम ने एक घण्टा खा लिया। आलम यह था कि न ही ट्रैफ़िक पुलिस का कोई सिपाही न ही कोई और इस जाम को खुलवाने का इच्छुक दिखा। सबकी तरह मैं भी उल्टी गाड़ी चलाकर और कुछ लम्बा घूमकर यमुना एक्सप्रेस वे पर पहुंच गया। थोड़ी देर में जेवर टोल नाके पर पहुंच कर पता चला कि जो टोल टैक्स कुछ समय पहले तक 325 रुपया एक तरफ़ का था (यदि मैं भूल नहीं रहा) वह अब बढकर 415 रुपया हो गया है।

सरपट दौड़ती मेरी कार तब धीमी हो जाती जब सड़क पर दसियों गाड़ियां दुर्घटनाग्रस्त होकर औंधी मुंह पड़ी दिखती। मस्तिष्क में कौंध जाता था कि क्या-क्या कारण होंगे ऐसी दुर्घटनाओं के? क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे सीमेंट (कंक्रीट) रोड है इसलिये इस पर पहिये का घर्षण अधिक है बनिस्पत अन्य सड़कों के। इस कारण टायर की हवा गर्म होकर ज़्यादा फ़ैलने की कोशिश करती है तथा टायर फ़ट जाता है। यह एक मुख्य कारण है इस सड़क पर दुर्घटना का।

तो क्या टोल वसूलने वाली जे.पी. ग्रुप, सरीखी कम्पनियों की इतनी नैतिक या विधिक जिम्मेवारी नहीं बनती कि टोल रोड के प्रवेश पर ही गाड़ियों के पहिये की हवा सुनिश्चित कराई जाए? क्योंकि इस साधारण से विज्ञान की समझ हमारे समाज में गाय के गोबर वाले विज्ञान से पट चुकी है।

यमुना एक्सप्रेस वे समाप्त हुआ तो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस वे की शुरुआत 570 रुपये का टोल टैक्स चुकाने से हुई। 317 किलोमीटर की सड़क पर खाने-पीने एवं ईंधन की व्यवस्था नदारद थी। बीच में दो स्थानों पर प्रसाधन व्यवस्था का काबिले तारीफ़ बंदोबस्त तो था परन्तु सन्नाटे से उत्पन्न असुरक्षा की कोई काट नहीं दिखाई देती थी दूर-दूर तक। पी.सी.आर. वैन के नाम पर 100 डायल का शोर मचाने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की यहां सुरक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि प्राकृतिक शौच न जाना हो तो भी डर से शौच निकल जाए। हां इतने तेज एक्सप्रेस वे पर सांडों के झुंड जरूर दिख रहे थे। यानी कि 570 रुपये दीजिये और जान पर खेल कर लखनऊ पहुंचने के एडवेन्चर का अनुभव कीजिए।

100 किलो मीटर प्रति घण्टे की रफ़्तार से पहुंचने का अनुभव 360 डिग्री विपरीत मोड़ ले गया जब यह पाया कि लखनऊ में सारे शहर के ट्रैफ़िक को पार करके गोरखपुर रोड पर पहुंचना होगा।

यानी जो समय वहां पैसा देकर बचाया वो यहां खर्च किया। योगी सरकार के आने से आये रामराज्य में चौराहों पर चार-चार ट्रैफ़िक सिपाहियों के होते हुए भी वाहन आपस में सांडों की भांति गुत्थमगुत्था करने पर उतारू हैं, और न जाने कैसे सब आपस में लड़-भिड़ कर जीवित निकल जा रहे हैं। भरतीय बैंकों सी जर्जर अवस्था लिए बिक्रम (टैम्पो) 10-10 सवारियां ढो रहे हैं, मानो इन विक्रमों का जन्म ही सड़कों का बलात्कार करने के लिये हुआ है। भला हो उन ठेले, और रिक्शेवालों का जिन्होंने लखनऊ शहर से होकर गोरखपुर रोड पर पहुंचने का मार्गदर्शन किया। अन्यथा मार्गदर्शक बोर्ड के नाम पर हाशमी दवाखाना, गुप्तरोग विशेषज्ञ, नीम-हकीमों व नेताओं के हाथ जोड़े बोर्ड ही थे। शायद सरकारें मान चुकी हैं कि भारत अब डीजिटल हो गया।

लखनऊ की भूल-भूलैया से गोरखपुर रोड पर आ तो गए परन्तु इस 240 कि.मी. के सफ़र में लखनऊ से बनारस रोड तक आने पर पांच टोल नाके पड़े। हर 50 कि.मी. पर एक टोल नाका! कुल देय राशि 350 से 400 रुपये के बीच उगाही गई। इतना देने के बाद भी अपनी जान बचाकर गंतव्य स्थान पर पहुंचना आपकी अपनी जिम्मेवारी है। क्योंकि दोनों सड़कों के बीच से वो झाड़ियां व अवरोध ज्यादातर नदारद ही हैं जो सामने आने वाली गाड़ी की हाई बीम से आपको बचाएं। ऊपर से गौवंश की माताओं, पिताओं, बहनों के साथ-साथ भैरो बाबा की सवारियों का उन्मुक्त विचरण भी।

इन खूनी व लूटेरी टोल रोडों से उतरकर अब मैं बनारस रोड, जो मेरी बचपन की स्मृतियों में शामिल है, पर आ गया। इस सड़क पर आम, पीपल, गूलर, जामुन, महुआ के मोटे-मोटे पेड़ इसे प्राचीन गुफ़ा सा चिन्हित करते थे। लेकिन यह क्या? सड़क पर एक भी पेड़ नहीं, सब के सब कट चुके हैं। एक नए टोल रोड की तैयारी है, जिसे तथाकथित चौड़ा करने के नाम पर पेड़ों को काट डाला गया है। मेरी स्मृतियों को बारम्बार प्रगाढ़ करने वाले इन पेड़ों की अनुपस्थिति ने मेरी चेतना को धूमिल करने का पूंजीवादी खेल प्रारम्भ कर दिया।

गांव पहुंचकर मोदी भक्तों से पता चला कि यह वृक्ष-विहीनता, विकास की अवधारणा से लैस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, तभी तो देश विकास करेगा। मोदी-योगी की जोड़ी इस देश की सूरत बदल देगी। इत्यादि-इत्यादि।

मन ही मन सोचता रहा कि इन भोले-भाले (या बेवकूफ़ कहूं तो ज्यादा बेहतर होगा) लोगों को कारपोरेट और बिकाऊ मीडिया ने कैसा भरमाया है कि देश की सूरत कितनी बदसूरत होगी इसका अंदाजा भी नहीं इन्हें। विनाश को विकास समझकर मूल सवाल ही भूले बैठे हैं।

क्या बिना पेड़ों को काटे दूसरी सड़क उतनी जगह छोड़कर नहीं बन सकती थी? क्या प्रति व्यक्ति आय इतनी शानदार हो गई है कि सड़कों पर सिर्फ़ मोटर कारें, बसें ही दौंड़ेगी जो ग्रीन हाउस गैसों का गुल्लक हैं? साइकिल सवार, पैदल यात्री, पशु-पक्षी गरीब जो पेड़ की छाया में सुस्ताते थे अब वहां से न निकलें या घोसले न बनाएं?

इन्हीं प्रश्नों के साथ-साथ एक प्रश्न यह भी है कि जिस सड़क पर ट्रैफ़िक फ़ोर लेन तक का ही है उसे अकारण छः लेन का क्यों करना है? जनसंख्या का पलायन शहरों में है और सड़कें हम बाहर भी चौड़ी करते जा रहे हैं। वहीं शहरी सड़कें, पुलिस एवं नगर निगम के बावजूद अतिक्रमण से पटी पड़ी हैं। सड़कों पर कारों के बहते ट्रैफ़िक को सुलभ एवं सुगम सार्वजनिक परिवहन (बसों) से क्यों नहीं कम किया जा रहा?

गांव के झगड़ों में सुना था कि 'सड़क तुम्हारे बाप की नहीं है, सबकी है।' इतनी छोटी सी उम्र में यह देख लिया मैंने कि सड़क सबकी नहीं है। संबित पात्रा ने नरेन्द्र मोदी को सबका बाप घोषित कर ही दिया है। और मोदी सरीखे अन्य मोदियों ने कॉरपोरेट की शक्ल में अपने-अपने बाप भी तय कर लिये हैं। जी हां, सड़क अब बाप की है जो हर 50 कि.मी. पर आपसे टोल टैक्स लेगा जिसके बाद गड्ढों, सूअरों, सांडों, गायों, उल्टी दिशा में आते वाहनों से बचने की जिम्मेवारी आपकी।

अब तो कभी-कभी 50 कि.मी. से ज्यादा रास्ता बिना टोल गेट आने पर शक होता है कि माजरा क्या है? और, गालिब का शेर याद आता है:

खुदा के वास्ते परदा नक़ाब
से उठा ज़ालिम
कहीं ऐसा न हो, यह भी
काफ़िर सनम निकले

दयनीय स्थिति है कि विकास के नाम पर वाहनों को अंधाधुंध बढावा और सड़कों को टोल टैक्स वसूलने के लिये चौड़ा करने का गोरखधंधा बदस्तूर जारी है। इस विकास की भेंट पर, पेड़ कट-कट कर चढ रहे हैं तो वहीं पेरिस समझौतों में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने की हमारे मोदियों की लफ़्फ़ाज़ी भी इसी अनुपात में जारी है।

तो हमें अब जान लेना चाहिये कि सड़क सबकी नहीं है, सड़क उसकी है जो इस पर चलने की (तय शुदा लूट की) राशि अदा करेगा। अन्यथा, जहां हो वहीं बैठे रहो, आपको हुई असुविधा के लिये खेद है। हमने तो दोनों ओर की यात्रा के करीब तीन हज़ार रुपये अदा कर दिये और सलामत लौट भी आये।

धन्यवाद नितिन गडकरी!